किन-किन राज्यों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से लगभग 155 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक समझौता किया है। इस परियोजना के तीन प्रमुख घटक हैं (1) अपनी-अपनी प्रदूषण निगरानी संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहायता, (2) साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु उद्योगों के समूहों को सहायता तथा (3) प्रदूषण शोधन प्रणालियां स्थापित करने/उनके सुधार करने के लिए बड़ी और मंझौली इकाइयों को ऋण के रूप में सहायता। यह परियोजना 6 नवम्बर, 1991 को लागू हो गई है। इस परियोजना पर व्यय 1992 से शुरू हो जाने की संभावना है।

रासायनिक उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इस परियोजना के तहत उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीधे ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, रासायनिक उद्योगों सहित लघु उद्योगों के समूहों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए भी सहायता उपलब्ध है।

Regularisation of Encroachment

2808. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 26 given in the Rajya Sabha on the 20th November, 1991 and state:

(a) from whom the proposals have been received for regularisation of encroachment under Forest (Conservation) Act, and

(b) the exact details of all the proposals?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Proposals for regularisation of encroachments under the Forest (Conservation) Act, 1980 have been received from the State/UT Government of Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andaman & Nicobar Islands.

(b) The details of the proposals are as under:—

(i) **Kerala**—A proposal has been received for regularisation of encroachments over 28,588.159 hectares of forest land in four districts.

(ii) **Madhya Pradesh**—46 proposals have been received for regularisation of encroachments over 2,73,468. 370 hectares of forest land in 45 districts.

(ii) **Maharashtra**—A proposal has been received for regularisation of encroachments over 350.32 hectares of forest land in Dhule district.

(iv) **Andaman & Nicobar Islands**—Four proposals have been received from the Andaman and Nicobar Administration for regularisation of encroachments over 1367 hectares of forest land in North Andaman, Baratang, South Andaman and Middle Andaman Islands.

आदिवासी क्षेत्रों में वन माफिया

2809. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में वन माफियां के सक्रिय होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ क्या कार्यवाहीं की गई है तथा कार्यवाही